

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1746
उत्तर देने की तारीख-13/02/2023

विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी

†1746. डॉ. डी. एन.वी. सेंथिलकुमार एस. :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की देश में सभी विद्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की मंशा है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए प्रयासों, प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा अब तक हुई प्रगति की स्थिति क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा;
- (घ) तमिलनाडु राज्य में कितने विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्शन हैं, साथ ही कितने विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब तथा बैठने की पर्याप्त क्षमता है;
- (ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्ष-वार इस प्रयोजन के लिए तमिलनाडु को आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सरकार से अधिक से अधिक विद्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बीएसएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर करने और कंप्यूटिंग उपकरणों वाले सभी सरकारी स्कूलों को एफटीटीएच इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु एडवायजरी जारी की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि इंटरनेट शुल्क निम्नलिखित से पूरा किया जा सकता है:

- समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत आईसीटी लैब्स/स्मार्ट क्लास रूम के लिए इंटरनेट शुल्क समग्र शिक्षा के तहत जारी किए जा रहे आवर्ती शुल्क से पूरा किया जा सकता है।
- जिन स्कूलों में समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी/स्मार्ट क्लास रूम स्वीकृत नहीं हैं और जिनके पास कंप्यूटिंग डिवाइस हैं, इंटरनेट शुल्क समग्र शिक्षा के तहत जारी की जा रही प्रबंधन निगरानी मूल्यांकन और अनुसंधान (एमएमईआर) निधि से पूरा किया जा सकता है या किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से पूरा किया जा सकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में इंटरनेट सुविधा का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(घ) से (च): समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित फंड शेयरिंग पैटर्न के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, वार्षिक योजनाएँ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) प्रस्तावों में परिलक्षित होता है। इसके बाद योजना के कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों तथा पहले अनुमोदित कार्यकलापों के लिए राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा, समग्र शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन और खरीद (एफएमपी) नियमावली के तहत निर्धारित लेखापरीक्षित लेखा, उपयोगिता प्रमाण पत्र, वास्तविक और वित्तीय प्रगति और अन्य दस्तावेजों को जमा करने के आधार पर निधि जारी की जाती है।

तमिलनाडु राज्य में 9292 सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा और 5815 सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब हैं। पिछले 3 वर्षों में तमिलनाडु राज्य में वास्तविक और वित्तीय दोनों में स्वीकृत आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास रूम का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. डी. एन.वी. सेंथिलकुमार एस. द्वारा दिनांक 13.02.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1746 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सरकारी विद्यालय	इंटरनेट सुविधा वाले विद्यालय
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	342	133
आंध्र प्रदेश	45137	20313
अरुणाचल प्रदेश	2985	458
असम	45490	4680
बिहार	75558	4421
चंडीगढ़	123	123
छत्तीसगढ़	48743	16469
दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव	388	194
दिल्ली	2762	2762
गोवा	814	299
गुजरात	34699	32681
हरियाणा	14562	4345
हिमाचल प्रदेश	15380	4175
जम्मू और कश्मीर	23173	5169
झारखंड	35840	12052
कर्नाटक	49679	5308
केरल	5010	4738
लद्दाख	838	342
लक्षद्वीप	38	37
मध्य प्रदेश	92695	16469
महाराष्ट्र	65639	18540
मणिपुर	2889	340
मेघालय	7783	1111
मिजोरम	2563	153
नागालैंड	1960	850
ओडिशा	49072	3970
पुदुचेरी	422	422
पंजाब	19259	9013
राजस्थान	68948	36889
सिक्किम	864	231
तमिलनाडु	37636	9292
तेलंगाना	30023	2772
त्रिपुरा	4262	682
उत्तर प्रदेश	137024	12074
उत्तराखंड	16484	2575
पश्चिम बंगाल	83302	12918
भारत	1022386	247000
स्रोत यूडाइज+ 2021-22		

अनुलग्नक-II

विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. डी. एन.वी. सेंथिलकुमार एस. द्ववारा दिनांक 13.02.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1746 के भाग (घ से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(वित्तीय करोड़ में)

राज्य	2019-20 में आईसीटी लैब		2020-21 में आईसीटी लैब		2021-22 में आईसीटी लैब	
	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
तमिलनाडु	-	-	441	54.29	1893	149.87

(वित्तीय करोड़ में)

राज्य	2019-20 में स्मार्ट क्लासरूम		2020-21 में स्मार्ट क्लासरूम		2021-22 में स्मार्ट क्लासरूम	
	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
तमिलनाडु	-	-	-	-	865	20.76
